



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 468 राँची, गुरुवार, 15 आषाढ़, 1938 (श०)
6 जुलाई, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

25 मई, 2017

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, कोडरमा का पत्रांक-173/स्था०, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 एवं पत्रांक-414/स्था०, दिनांक 9 मई, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-6894, दिनांक 7 जुलाई, 2014

संख्या- 5/आरोप-1-272/2014 का.-6517-- श्री हीरा कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला-राँची) के विरुद्ध श्रीमती सुनीता देवी, प्रमुख, प्रखण्ड पंचायत समिति, मरकच्चो, कोडरमा तथा मो० नसीम अंसारी, सदस्य, प्रखण्ड पंचायत समिति, प्रखण्ड-मरकच्चो, कोडरमा से परिवाद पत्र प्राप्त है। इसके आलोक में उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-173/स्था०, दिनांक 30 अप्रैल, 2014 द्वारा श्री कुमार विरुद्ध

प्रतिवेदित आरोपों की जाँच कर प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप सं०-1. मरकच्चो प्रखण्ड के पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा आपके विरुद्ध परिवाद-पत्र देकर यह आरोप लगाया गया है कि आप 26 जनवरी, 2013 को संपन्न गणतंत्र दिवस समारोह के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद उपस्थित हुए एवं पत्रकारों एवं छायाकारों से अपना फोटो खिंचवाया। इस संबंध में श्री भोगेन्द्र ठाकुर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा ने आपके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को जाँचोपरांत सत्य पाया है एवं पत्रांक-417, दिनांक 12 जून, 2013 से इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन पर आपसे पत्रांक-2172/गो०, दिनांक 24 जून, 2013 से लिखित कारण पृच्छा की माँग भी की गयी, परन्तु आपने कारण पृच्छा का उत्तर देना उचित नहीं समझा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पर्व जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर झंडोत्तोलन के समय उपस्थित नहीं रहकर अपने कर्तव्यहीनता का परिचय दिया है।

आरोप सं०-2. जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायत समिति की बैठक बुलाए जाने हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद पंचायत समिति की बैठक नहीं बुलाये जाने का गंभीर आरोप आपके विरुद्ध पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाया गया। इस संबंध में श्री भोगेन्द्र ठाकुर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा ने पत्रांक-417, दिनांक 12 जून, 2013 से इस संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आपके द्वारा पंचायत चुनाव के बाद मात्र एक बार ही दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को विधिवत् बैठक की गयी है। इस प्रकार आपके विरुद्ध लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

आरोप सं०-3. पंचायत जनप्रतिनिधियों द्वारा 13वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं किये जाने का आरोप आपके विरुद्ध लगाया गया है। इसकी जाँच श्री भोगेन्द्र ठाकुर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा से करायी गयी एवं उनके द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन पत्रांक-417, दिनांक 6 जुलाई, 2013 द्वारा समर्पित किया गया है। जाँच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि रोकड़ पंजी के अनुसार, 44,72,041/- ₹० में से 5,04,123/- ₹० की राशि का व्यय कुर्सी, पंखा इत्यादि क्रय करने में किया गया है। शेष राशि 39,67,918/- ₹० रोकड़ पंजी में अवशेष दर्ज पाया गया है, जिसके विरुद्ध एक भी योजना नहीं ली गयी है। इस प्रकार लगाया गया आरोप सत्य पाया गया है।

आरोप सं०-4. श्री बबलू कुमार, पिता-स्व० ईश्वर प्रसाद, ग्राम+थाना-मरकच्चो द्वारा 50,000/- ₹० घूस माँगने एवं मानसिक प्रताड़ना के संबंध में दिये गये परिवाद पत्र पर श्री भोगेन्द्र ठाकुर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा से जाँच करायी गयी। उनके द्वारा पत्रांक-531, दिनांक 27 जुलाई, 2013 से प्रतिवेदित किया गया है कि गैर-मजरूआ खास भूमि पर पूर्णतया स्थायी/अस्थायी रूप से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने हेतु श्री बबलू कुमार एवं श्रीमती सुदामा देवी के विरुद्ध मात्र एक ही वाद दायर किया गया है, जबकि Pubilc land Encroachment Act में निहित प्रावधानों के तहत

पूरे मकानों-दुकानों को चिह्नित करते हुए सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अतिक्रमणवाद कायम कर नोटिस निर्गत किया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं किया गया। इस संबंध में कार्यालय पत्रांक-2555/गो०, दिनांक 1 अगस्त, 2013 से आपसे कारण पृच्छा की गयी, परन्तु आपके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि निजी स्वार्थवश आपके द्वारा लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों का भेदभावपूर्वक इस्तेमाल किया गया है, जो सरकारी पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है।

आरोप सं०-5. कार्यालय पत्रांक-2172/गो०, दिनांक 24 जून, 2013, दिनांक 2552/गो०, दिनांक 1 अगस्त, 2013 एवं पत्रांक-2555/गो०, दिनांक 1 अगस्त, 2013 द्वारा विभिन्न आरोपों के संबंध में आपसे लिखित कारण-पृच्छा की गयी, परन्तु आपके द्वारा एक भी कारण पृच्छा का उत्तर देना उचित नहीं समझा गया। इससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की जाती है। यह आपके कर्तव्यहीनता का द्योतक है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-6894, दिनांक 7 जुलाई, 2014 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। आरोपों के संबंध में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि प्रताड़ित करने की मंशा से सारे आरोप वैमनस्यता के कारण लगाये गये हैं तथा इनके द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-414/स्था०, दिनांक 9 मई, 2016 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, कोडरमा का मंतव्य निम्नवत् है:-

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- श्री कुमार के जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे झंडोत्तोलन के वक्त थे अथवा बाद में आए थे तथापि इस आरोप से यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं श्री कुमार तथा प्रमुख के बीच समन्वय की कमी थी। कहीं न कहीं यह आरोप राजनीति से प्रेरित मालूम पड़ती है। साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत फोटोग्राफ स्वीकार योग्य है। इसमें किसी प्रकार की टेम्परिंग नहीं है।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- आरोप एवं श्री कुमार के जवाब से प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं श्री कुमार तथा प्रमुख के बीच सामंजस्य की कमी थी। यह दोनों का दायित्व था कि ससमय बैठक हो। अतः तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए इनका स्पष्टीकरण स्वीकारयोग्य कहा जा सकता है।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- उपायुक्त का मंतव्य है कि उस समय जनप्रतिनिधियों द्वारा अग्रिम राशि की माँग की जा रही थी। श्री कुमार का जवाब संतोषप्रद प्रतीत होता है कि योजना पूर्ण होने के पश्चात् मापी पुस्त के आधार पर भुगतान किया जाना था। अतः उस वक्त राशि खर्च नहीं हुई थी।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- श्री कुमार के द्वारा लोक अतिक्रमण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गयी। दुर्भाग्य से जिनके विरुद्ध यह कार्रवाई की गयी, उन्हीं के द्वारा यह आरोप लगाया

गया तथा इस संबंध में तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा सम्यक् जाँच नहीं की गयी । अतः इनके जवाब को स्वीकृत किया जा सकता है ।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- कहीं न कहीं यह पूरा प्रकरण श्री कुमार तथा श्री भोगेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा-सह-वरीय पदाधिकारी, मरकच्चो प्रखण्ड के बीच खराब प्रशासनिक माहौल का परिणाम प्रतीत होता है तथापि श्री कुमार द्वारा कारण-पृच्छा का जवाब नहीं दिया जाना उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन को प्रमाणित करता है ।

श्री हीरा कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, कोडरमा के मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षा में पाया गया कि उपायुक्त, कोडरमा द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध पाँच आरोपों में से मात्र एक को प्रमाणित पाया है, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सामान्य कहा जा सकता है ।

अतः समीक्षोपरान्त, श्री कुमार को भविष्य में सचेत रहने हेतु चेतावनी संसूचित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
